पूछ रही हूं । महोदया, मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को रा मेटिरियल मुहैया कराया जाएगा और उसके लिए उन्होंने केरल सरकार से बातचीत भी की है ।

मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूं लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि हमारा हिन्दुस्तान का जो न्यूज प्रिंट होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है । तो उसके क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैन्टेन करने का इन्होंने कोई मानदंड बनाया है ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं मंत्री जी से कि जो रा मैटिरियल ठीक समय पर मिल जाए इसके लिए कोई उपाय इन्होंने किया है, निश्चित उपाय किया है क्योंकि बातचीत तो हो जाएगी और केरल सरकार समय पर अगर मुहैया नहीं कराएगी रा मैटीरियल, कच्चा माल तो फिर यह कारखाना बैठने को हो जाएगा । मैंने सवाल में यह भी कहा था कि . . . (व्यवधान) इसको एक प्राइवेट कारखाने को देने वाले हैं, क्या यह सही है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

Mr. Minister, you may reply to her within one month.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन

@@584. **श्री विनोद शर्मा :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा नीति निदेशों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया है और 1990-91 तथा 1991-92 के लिए नियत किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है ;

(ग) क्या जवाहर रोजगार योजना का स्वतन्त्र एजेन्सियों से मूल्यांकन कराये जाने का विचार है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या किन्हीं राज्यों ने उन्हें मूलतः जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित की गई राशि को किन्हीं दूसरी मदों के लिए अन्तरित किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिकाओं और नीति निर्देशों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना 1-4-1989 से सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) सभी राज्य जवाहर रोजगार योजना के मैन्यूअल में दी गई मार्गदर्शिकाओं और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों का पालन भी कर रहे हैं । योजना की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक राज्य में सृजित श्रम दिवसों के रूप में की जाती है । 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों और सृजित रोजगार को अनुपत्र में दर्शाया गया है । [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या 81]

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के उल्लिखित उद्देश्यों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 33 स्वतन्त्र अनुसंधान संस्थाओं की मार्फत

@@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 464, 10 अगस्त, 1992 से स्थानांतरित ।

जवाहर रोजगार योजना का एक समवर्ती मूल्यांकन शुरु किया है । मूल्यांकन के मुख्य ब्यौरे सृजित रोजगार की मात्रा और स्वरूप, श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, सृजित परिसम्पत्तियों और समुदाय तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी लाभप्रदता तथा योजना को कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में हैं । मूल्यांकन कार्य देश के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है और इसके वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(घ) निधियों का ऐसा कोई अन्तरण भारत सरकार की जानकारी में नहीं आया है । यदि ऐसा कोई मामला ध्यान में आयेगा तो राज्य सरकार से निधियों की वसूली की जाएगी ।

Partictpation of Trade Unions in the Indian Labour Conference

5B. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state;

(a) what are the criteria fixed by Government for the trade unions to be able to participate in the Indian Labour Conference;

(b) whether, besides the Central Trade Unions, the independence trade unions federation^, operating on the national level will also be allowed to participate in the ensuing Indian Labour Conference; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINIS TER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA); (a).to (c) On the basis of the recommendations of the National Labour Conference held on 17-18 September, 1982, the following decisions regarding representation of Trade Unions on Indian Labour Conference were taken :—

(i) Only Trade Union Organisations which have a membership of more than five lakh spread over 4 States and 4 Industries would have representation in the Indian Labour Conference.

(ii) Organisations which are not affiliated to any of the Central Trade Union Organisations would not be invited.

However, on consideration of the representations received by the Government it was decided that smaller Central 'Trade Union Organisations having membership of more than one lakh and less than five lakhs may also be given representation on the Indian Labour Conference. Accordingly, the Central Trade Union Organisations having membership strength of more than 5 lakh$_s$ are provided seats pro-rata on the basis of the verified membership figures of each Central Trade Union Organisation. The Central Trade Union Organisations with a verifier membership of more than on$_e$ lakh but less than five lakhs are provided only one seat each in the Indian Labour Conference.

3. The criteria for representation of Workers' Organisations at the; Indian Labour Conference were again considered by the 28th Session of the Indian Labour Conference held on 25-26 November, 1985. The Conference felt that the matter relating to criteria for workers' representation on the Indian Labour Conference should be left to be decided by the Central Trade Union Organisations theateelves and in the case of any difference among them, Government would take a decision in the matter.

4. For the 29th session of the Indian Labour Conference held on 21-22, April 1990 representation was given as per paras 2 and 3 above. For the 30th Session proposed to be held on the 7th & 8th September, 1992, it has been decided to give representa-